वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा अन्य अधिकारियों ने 10/11 फरवरी, 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिये जयपुर की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान, राज्य सरकार की पूर्व प्रार्थना पर, वे लोग 11 फरवरी, 1978 को मुख्य मंत्री से मिले थे।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में उठाये गये प्रमुख विषय ये थे —

(1) राज्य सरकार के "अन्त्योदय" कार्यक्रम का वित्तीय सहायता देने के बारे में समस्याये।

(2) राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को वित्तीय सहायता।

(3) राजकीय परिवहन निगम द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइया।

(4) राजस्थान में गैर बैंकिंग उपखजानों को बैंकिंग खजानों में परिवर्तित करना।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन मुद्दों की जांच की जा रही है।

Relaxation of Gold Control Order

*359 SHRI DHARAM VIR VASISHT.

SHRI PRADYUMNA BAL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the provisions of Gold Control Order relaxed recently by the Government, together with relief if any to the genuine ornament wearers; and

(b) whether Government propose further relaxation or scrapping the gold control order, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL): (a) and (b). Certain relaxations within the ambit of the Gold (Control) Act and the Rules thereunder have been given to certified goldsmiths by issue of notifications/orders on 14-2-1978 According to these relaxations a certified goldsmith can—

(i) manufacture and sell ornaments out of the standard gold bars which he is already allowed to possess against specific orders from the customers

(ii) make small purchases upto 35 grams of ornaments at a time from a person and utilise the same for the purpose of making, manufacturing ornaments against specific orders from other customers,

The goldsmiths availing of the above concessions are required to have a fixed place of business and maintain the prescribed accounts

(iii) The present restrictions regarding issue of goldsmith's certificates only to the members of family of goldsmiths have been removed Now any person who possesses necessary skill of a goldsmith and who has worked with a certified goldsmith as an apprentice for a period not less than 3 months and who has not been disqualified on account of conviction or imposition of penalty for gold control or smuggling offences is eligible to get a goldsmith's certificate

2 Finance Minister in his budget speech announced the Government's decision to sell gold from the stocks held by it primarily as an anti-smuggling measures Such sales of gold from Government's stocks is expected

also to bring down the domestic price of gold.

3. Government do not propose to scrap the Gold Control Act. However, to make the administration of gold control more effective, amendments to rules framed under the Act are made from time to time. These amendments are also intended to meet the changing situations and in response to various representations received from Associations of Goldsmiths and Dealers.

Supply of Rapeseed Oil to Kamal Oil Mills and Capital Mill, Delhi

*360. DR. BALDEV PRAKASH:

DR. LAXIMINARAYAN PANDEYA:

Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether Rapeseed oil was supplied to firms namely Kamal Oil Mill and Capital Mill, Delhi in spite of the fact that these were black listed by Delhi Administration and their licences cancelled as appeared in *'Nav-Bharat Times'* dated 22nd February, 1978; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) No, Sir. The Central Government did not supply any rapeseed oil to Kamal Oil Mill or Capital Mill for refining.

(b) Does not arise.

गांवों के विकास के लिए करों में छूट

*361. श्री राम सागर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार किसी ऐसी फर्म अथवा स्वयं सेवी संगठन को करों में छूट देने का है जो किसी खंड विशेष को उसके सर्वतोमुखी, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए तथा वहां बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). कम्पनियों और सहकारी समितियों को, ग्रामीण-क्षेत्रों में कल्याण और सुधार कार्य जुटाने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35–ग ग के अधीन कर सम्बन्धी रियायतों की व्यवस्था की गई थी।

वित्त विधेयक, 1978 में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि व्यापार अथवा वृत्ति में लगे जो करदाता ग्रामीण-क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगठनों और संस्थाओं को धन देते है, उन्हें कर सम्बन्धी रियायत दी जाय। ऐसा आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा, 35ग ग क, अन्तःस्थापित करके करने का प्रस्ताव है।

धारा 35ग ग और प्रस्तावित धारा 35 ग ग क के अधीन उपलब्ध कर सम्बन्धी रियायतों का एक विवरण-पत्र, सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35ग ग ग्रामीण-क्षेत्र में विकास के लिए छूट

वित्त (संख्या2) अधिनियम 1977 द्वारा आय-कर अधिनियम 1961 ; अन्तस्थापित धारा 35–ग ग के अन्तर्गत कम्पनियां